दूरदर्शन एवं रंगीन दूरदर्शन के विस्तार में अधिक संसाधन लगाने में विभाग को कोई वित्तीय कठिनाई नहीं आती परन्तु विभाग सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न कर उनकी घोर उपेक्षा कर रहा है ।

14.54 hrs.

[SHRI HARINATH MISRA *in the chair*

सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को देश की प्रगति की जानकारी से वंचित रखना उनके साथ घोर अन्याय है । ये क्षेत्र देश के प्रहरी हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण की सेवा का लाभ देना केन्द्र सरकार का प्रथम कर्तव्य है ।

अतः सूचना एवं प्रसारण मंत्री आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वे छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करा कर सीमावर्ती क्षेत्र की जनता की आवश्यक से आवश्यक मांग की पूर्ति करें, और देश के महत्वपूर्ण स्थानों में शक्ति वाले ट्रान्समीटर लगा कर देश की आवश्यक मांग की पूर्ति करें ।

(iii) SHORTAGE OF DRINKING WATER IN CERTAIN HILLY DISTRICTS AND BUNDELKHAND AREA OF U.P.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वर्तमान दशक को अन्तरर्राष्ट्रीय पेयजल दशक के रूप में मनाने का सरकार का निश्चय निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है । पेयजल के महत्व, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी के नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी पेयजल आपूर्ति को महत्व दिया गया है ।

परन्तु यह कार्य बहुत मन्थर गति से चल रहा है । साथ ही पेयजल अभावग्रस्त गांवों की जो सर्वेक्षण सूची 1971 के सर्वेक्षण के आधार पर बनी है उसकी पुनरावृत्ति 1981 या नये सर्वेक्षण के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि 1971 के बाद प्राकृतिक व मानवजन्य कारणों से कई गांव पेयजल अभावग्रस्त हो चुके हैं । मैं समझता हूं कि कई राज्य सरकारों द्वारा भी इस सूची में परिवर्धन की मांग की गई है । इस कार्य में जितने धन की व्यवस्था की गई है वह भी सर्वथा अपर्याप्त है । इसे भी बढ़ा कर चौगुना किया जाना आवश्यक है ।

उत्तर-प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल के अभाव की भयावह स्थिति है । यदि शासन द्वारा शीघ्र कोई ठोस प्रोग्राम इस हेतु नहीं बनाया गया तो लोगों को अपने गांवों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

अतः मेरा आवास एवं निर्माण मंत्रालय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही की जावे ।

(iv) NEED FOR OPENING MORE COLLEGES IN DELHI.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Sir, in spite of claims by the Government and the Delhi University Authorities that seats are available in various courses, it is now clear on facts and figures that over 15000 students do not stand any chance to get admitted in Delhi. Over 11000 students have secured over 80 per cent marks, while 12000 are between 50 per cent and 60 per cent marks. Against this, there are only about 22800 seats in all the courses in all the colleges. What will be the fate of all those students who are below 50 per cent marks. Apart from